कृषि नवाचार
ISSN: 3048-6092
https://www.krishinavachar.in
खण्ड 02 भाग 04 जुलाई, 2025

# एग्रो-बिजनेस: ग्रामीण भारत की नई अर्थव्यवस्था

**पवन कुमार**
बी.एस-सी (ऑनर्स) कृषि, आर.एस.एम. (पी.जी.) कॉलेज, धामपुर, बिजनौर, उत्तर प्रदेश
**E-mail: pk2914290@gmail.com**

**भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां लगभग 60% जनसंख्या आज भी कृषि पर निर्भर है। परंतु पारंपरिक खेती के सीमित लाभ और अनिश्चितताओं ने कृषकों को आय के विविध साधनों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। ऐसे समय में एग्रो-बिजनेस ग्रामीण भारत के लिए एक नई उम्मीद और आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम बनकर उभरा है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि केवल जीवनयापन का साधन नहीं, बल्कि एक जीवनशैली है। आज जब पारंपरिक खेती सीमित आय और जोखिम से घिरी है, तब एग्रो-बिजनेस एक प्रभावी समाधान के रूप में सामने आया है। यह न केवल किसानों को उद्यमी बनने का अवसर देता है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नया आयाम प्रदान करता है।**

## एग्रो-बिजनेस क्या है?

एग्रो-बिजनेस का अर्थ है:- कृषि से जुड़ी व्यावसायिक गतिविधियाँ। यह केवल खेती तक सीमित नहीं होता, बल्कि फसल के उत्पादन से लेकर उसकी प्रोसेसिंग (संसाधन), पैकेजिंग, भंडारण, मार्केटिंग और बिक्री तक की पूरी प्रक्रिया को शामिल करता है।

एग्रो-बिजनेस का तात्पर्य कृषि आधारित उत्पादों के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन और वितरण से संबंधित व्यावसायिक गतिविधियों से है। इसमें कच्चे कृषि उत्पादों को मूल्यवर्धन कर बाजार में बेचना शामिल होता है, जिससे किसान केवल उत्पादक ही नहीं, बल्कि एक सफल उद्यमी भी बन सकता है।

## ग्रामीण भारत में एग्रो-बिजनेस की संभावनाएं

ग्रामीण भारत में एग्रो-बिजनेस की संभावनाएं अत्यधिक व्यापक और आशाजनक हैं। यहां कृषि उत्पादन की भरपूर उपलब्धता, सस्ती भूमि, परंपरागत ज्ञान, श्रमिक संसाधन और स्थानीय बाजार की मांग इसे विकसित करने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं। फल, सब्जियां, अनाज, दुग्ध उत्पाद, औषधीय पौधे और जैविक खेती जैसे क्षेत्रों में मूल्यवर्धन कर ग्रामीण युवा छोटे-छोटे एग्रो-बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सरकार की विभिन्न योजनाएं, जैसे मुद्रा लोन, FPO, PM FME आदि, इस दिशा में पूंजी और प्रशिक्षण का सहयोग भी प्रदान करती हैं। यदि सही तकनीक, विपणन और प्रशिक्षण से जोड़ा जाए, तो एग्रो-बिजनेस न केवल किसानों की आमदनी बढ़ा सकता है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर और सशक्त भी बना सकता है।

**प्रचुर कच्चा माल:** भारत के गांवों में धान, गेहूं, गन्ना, फल, सब्जियां, मसाले आदि का उत्पादन बड़े स्तर पर होता है।

**सस्ती भूमि व श्रम:** ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने की लागत शहरी क्षेत्रों की तुलना में कम है।

**सरकारी योजनाओं का सहयोग:** प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मुद्रा योजना, आत्मनिर्भर भारत अभियान आदि ने इस क्षेत्र को बढ़ावा दिया है।

## एग्रो-बिजनेस के प्रमुख क्षेत्र

एग्रो-बिजनेस के प्रमुख क्षेत्र विविध और लाभकारी हैं, जिनमें फूड प्रोसेसिंग ( जैसे अचार, जैम, सॉस बनाना), डेयरी उत्पादों का निर्माण, मशरूम और मधुमक्खी पालन, फल-सब्जियों की पैकेजिंग और कोल्ड स्टोरेज, जैविक खेती, बीज और खाद का व्यवसाय, तथा डिजिटल एग्री-मार्केटिंग शामिल हैं। ये क्षेत्र किसानों को केवल उत्पादक नहीं, बल्कि उद्यमी बनने का अवसर देते हैं और उन्हें उत्पादन से बाजार तक की पूरी श्रृंखला में भागीदार बनाते हैं।

**फूड प्रोसेसिंग (खाद्य प्रसंस्करण):** जैसे अचार, पापड़, जैम, जूस, टमाटर सॉस आदि बनाना।

**डेयरी व्यवसाय:** दूध, दही, घी, पनीर आदि का उत्पादन व ब्रांडिंग।

**फल-सब्जी कोल्ड स्टोरेज:** खराब होने वाले उत्पादों को संरक्षित कर बाजार में उचित मूल्य पर बेचना।

औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती और बिक्री।

**ऑनलाइन एग्रो-मार्केटिंग:** डिजिटल प्लेटफॉर्म से उत्पादों की बिक्री।

## युवाओं की भागीदारी और स्टार्टअप कल्चर

आज ग्रामीण भारत में युवाओं की भागीदारी और स्टार्टअप कल्चर तेजी से बढ़ रहा है। शिक्षा, तकनीक और इंटरनेट की उपलब्धता ने युवाओं को खेती को पारंपरिक पेशे से आगे बढ़ाकर एक लाभकारी व्यवसाय के रूप में देखने की सोच दी है। कई युवा अब एग्री-स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, जैसे कि फसल सलाह ऐप, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जैविक उत्पादों की ब्रांडिंग, आदि। स्टार्टअप जैसे DeHaat, Ninjacart और AgroStar इसका उदाहरण हैं, जो किसानों को बाजार, बीज, खाद, और तकनीकी सलाह सीधे मोबाइल से उपलब्ध करा रहे हैं। यह परिवर्तन न केवल रोजगार बढ़ा रहा है, बल्कि गांवों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी बना रहा है।

आज के युवा खेती को पुराना पेशा नहीं, बल्कि एक नया स्टार्टअप अवसर मानते हैं। कई सफल एग्रो स्टार्टअप्स जैसे DeHaat, Krishify, Ninjacart इत्यादि इसका प्रमाण हैं। ग्रामीण

युवा तकनीक और इनोवेशन से जुड़कर कृषि को लाभकारी व्यवसाय बना रहे हैं।

## महिला सशक्तिकरण में योगदान

एग्रो-बिजनेस ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभा रहा है। महिलाएं अब स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से अचार, पापड़, मसाले, मशरूम व जैविक खाद जैसे उत्पाद तैयार कर रही हैं। इससे उन्हें आय का स्रोत मिला है और आत्मनिर्भरता बढ़ी है। कई महिलाएं खेती-बाड़ी और विपणन में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं। यह बदलाव सामाजिक स्तर पर महिलाओं की स्थिति को भी सशक्त बना रहा है, साथ ही उन्हें निर्णय लेने की क्षमता और आर्थिक स्वतंत्रता भी प्रदान कर रहा है, जिससे वे परिवार और समाज में सम्मान के साथ अपनी भूमिका निभा रही हैं।

ग्रामीण महिलाएं स्वयं सहायता समूह (SHGs) के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण, मशरूम उत्पादन, हस्तशिल्प, मधुमक्खी पालन आदि में भागीदारी कर आत्मनिर्भर बन रही हैं और अपने परिवार की आय बढ़ा रही हैं।

## एग्रो-बिजनेस को बढ़ावा देने वाली योजनाएं

भारत सरकार द्वारा एग्रो-बिजनेस को प्रोत्साहित करने के लिए कई प्रभावी योजनाएं चलाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत युवाओं और महिलाओं को बिना गारंटी के ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिससे वे छोटे-छोटे एग्रो-उद्यम शुरू कर सकें। PM FME योजना (एक जिला एक उत्पाद) खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्रोत्साहन देती है। किसान उत्पादक संगठन (FPO) किसानों को संगठित कर सामूहिक उत्पादन और विपणन की सुविधा प्रदान करता है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के तहत नवाचार और स्टार्टअप्स को अनुदान दिया जाता है। एनएबीएआरडी और आत्मा परियोजना के माध्यम से प्रशिक्षण व वित्तीय सहयोग मिलता है। साथ ही ई-नाम पोर्टल से किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, ग्रामीण रोजगार सृजित करना और कृषि को लाभकारी व्यवसाय में बदलना है।

**मुद्रा योजना:** लघु व मध्यम उद्यमों को बिना गारंटी ऋण।

**NAFED व FPO (किसान उत्पादक संगठन):** किसानों को बाज़ार से सीधे जोड़ने की पहल।

## चुनौतियाँ और समाधान

एग्रो-बिजनेस ग्रामीण भारत की नई अर्थव्यवस्था के रूप में तेजी से उभर रहा है। यह न केवल किसानों की आय बढ़ाने का माध्यम है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर रहा है। हालांकि, एग्रो-बिजनेस को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे सीमित संसाधन, बुनियादी सुविधाओं की कमी, और बाजार तक पहुंच का अभाव। इन समस्याओं के समाधान के लिए तकनीकी नवाचार, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, और सरकारी योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन आवश्यक है। साथ ही, किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों और प्रबंधन के प्रति जागरूक करना भी जरूरी है, ताकि वे अपनी उत्पादकता बढ़ा सकें और एग्रो-बिजनेस को एक स्थायी एवं समृद्ध मॉडल बना सकें। इसके अलावा, ग्रामीण युवाओं को एग्रो-बिजनेस से जोड़कर उन्हें स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना भी महत्वपूर्ण है, जिससे वे अपनी पहचान बना सकें और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। जब यह पूरी व्यवस्था सही दिशा में काम करेगी, तो न केवल किसानों की स्थिति सुधरेगी, बल्कि भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी आत्मनिर्भर और समृद्ध होगी। ऐसे में एग्रो-बिजनेस ग्रामीण भारत के विकास का सबसे बड़ा आधार बनकर उभरेगा।

## निष्कर्ष

एग्रो-बिजनेस ग्रामीण भारत के विकास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन चुका है। यह न केवल किसानों की आय बढ़ाने में मदद करता है, बल्कि ग्रामीण युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भर बनने के अवसर भी प्रदान करता है। चुनौतियों के बावजूद, सही योजनाओं और तकनीकी सुधारों के माध्यम से एग्रो-बिजनेस को मजबूत किया जा सकता है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में स्थिरता आएगी और सामाजिक-आर्थिक विकास की दिशा में एक नई क्रांति संभव होगी। इसलिए, एग्रो-बिजनेस को प्रोत्साहित करना और उसे समुचित समर्थन देना आज की जरूरत है ताकि ग्रामीण भारत सशक्त और समृद्ध बन सके। एग्रो-बिजनेस केवल एक आर्थिक गतिविधि नहीं, बल्कि यह ग्रामीण भारत के समग्र विकास की कुंजी है। यदि सही दिशा में प्रयास किया जाए तो यह न केवल किसानों की आय बढ़ा सकता है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।